(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि संचार विभाग द्वारा अपने ठेकेदारों की मार्फत "कुल्लु-मंडी राष्ट्रीय राजमार्ग" पर केबल फाइबर बिछाने हेतु खुदाई का काम समुचित ढंग से नहीं किया जा रहा है;

(ख) क्या सरकार को इस बात की भी जानकारी है कि उक्त काम को अव्यवस्थित रूप से किये जाने के फलस्वरूप जनसाधारण का चलना और वाहनों का आना-जाना खतरे से खाली नहीं है;

(ग) क्या यह सच है कि उपर्युक्त कारण से इस राजमार्ग पर अनेक छुट-पुट दुर्घटनाएं हो चुकी हैं और गत दो महीनों में इन खाइयों में गिरने से दो व्यक्तियों की मृत्यु भी हो चुकी है; और

(घ) यदि हां, तो विभाग द्वारा इन असुविधाओं को दूर करने और वहां ऐसी दुर्घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुखराम): (क) जी, नहीं। ठेकेदारों द्वारा कार्य व्यवस्थित ढंग से किया जा रहा है। जैसा कि देश के अन्य भागों में किया जा रहा है, कुल्लू-मंडी खण्ड में भी आप्टिकल फाइबर केबल ठेकेदारों के माध्यम से बिछाये जा रहे हैं।

(ख) जी हां। दुर्गम भू-भाग होने और इस क्षेत्र की सड़कें तंग होने के कारण तथा आप्टिकल फाइबर की सुरक्षा की जरूरत को ध्यान में रखते हुए, कार्य सुव्यवस्थित रूप से किया जा रहा है। तथापि, सड़क प्रयोक्ताओं के लिए सावधानी बरतना अनिवार्य हो गया है।

(ग) जी हां। अब तक न तो कोई ऐसा दृष्टान्त हमारे ध्यान में आया है और न ही राज्य सरकार से इस संबंध में कोई शिकायत हमें प्राप्त हुई है।

(घ) हिमाचल प्रदेश की, विशेषकर कुल्लू-मण्डी खण्ड की भौगोलिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए इस कार्य पर एक सहायक इंजीनियर के नेतृत्व में कर्मचारियों के एक दल द्वारा लगातार निगरानी रखी जा रही है। इसके अलावा चेतावनी की घडियां, चेतावनी बत्तियां और सावधान रहने के अनुदेशों वाले बोर्ड भी लगाये जाते हैं। यह कार्य मार्च, 1994 तक पूरा होने की संभावना है।

**97. [Transferred to 4th March 94].*

Foreign Exchange Earnings from Private Airlines

*98. SHRI M.A. BABY: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) the foreign exchange earnings made through each private airlines in India for the last twelve months; and

(b) the foreign exchange outflow of each private airlines in India for the same period?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (DR. ABRAR AHMED): (a) and (b) The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

Credit Delivery System in Rural Sector

*99. SHRI SUSHILKUMAR SAMBHAJIRAO SHINDE: SHRIMATI VEENA VERMA:

Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether the RBI has decided to modify the credit delivery system in the rural sector by providing a greater role to non-Government Organisations and self-help groups; and

(b) if so, what are the precise changes effected in this regard and what difficulties and shortcomings are proposed to be overcome thereby?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS) DR. ABRAR AHMED): (a) and (b) Reserve Bank of India (RBI) have reported that there is no proposal to modify the credit delivery system in rural sector. Banks continue to finance borrowers directly as hitherto. However, with a view to improving access of the poor to bank credit, it has been considered advantageous to link the rural